संख्याः 84 - भू0क्रय/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांक 14 अगस्त, 2006

विषयः–पावर एण्ड बैंकिंग कर्मचारी आवासीय स्वायत्त सहकारिता समिति को कर्मचारियों के आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु तहसील विकासनगर के ग्राम पीन्धा में भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–198/डी0एल0आर0सी0/2006 दिनांक 15 जुलाई, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पावर एण्ड बैंकिंग कर्मचारी आवासीय स्वायत्त सहकारिता समिति को कर्मचारियों के आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154(2) एंव उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील विकासनगर के ग्राम पीन्धा में कुल 150 बीघा (30 एकड़) भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे

....(2)

स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसको भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति मे भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हो।

6- प्रश्नगत प्रकरण में भूमि क्रय किये जाने के पश्चात यदि सम्बन्धित संस्था उक्त क्षेत्र मे प्रचलित महायोजना मे प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग यदि इससे भिन्न है तो उसे नियमानुसार परिवर्तित कराना सुनिश्चित करेगी।

7- आवास विभाग के अन्तर्गत प्रचलित उक्त क्षेत्र मे प्रचलित अधिनियमों एंव भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये निर्माण कार्य करायेगी।

8- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3- सचिव, आवास विभाग, उत्तरांचल शासन।
4- श्री कमल कान्त, सचिव, पावर एण्ड वैविंग कर्मचारी आवासीय स्वायत्त सहकारिता, 81 सुमननगर, देहरादून।
5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनुसचिव।